

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व निगरानी संख्या: 24 / 2023

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला— सिरौही

बनाम

अप्रार्थी

सुठाराम पुत्र केसाजी, जाति— मेघवाल, निवासी— जीरावल, तह. रेवदर, जिला—सिरौही के कायम मुकाम :-

1. पुराराम पुत्र सुठाराम, जाति—मेघवाल, निवासी— जीरावल, तह. रेवदर, जिला—सिरौही
2. रमीलादेवी पत्नी उमाराम, जाति— मेघवाल, निवासी— जोलपुर, तहसील— रेवदर
3. रतीदेवी पत्नी दिनेशकुमार, जाति—मेघवाल, निवासी— जिला उद्योग केन्द्र, सिरौही
4. उषादेवी पत्नी नारायण, जाति—मेघवाल, निवासी—निम्बज, तह. रेवदर, जिला—सिरौही
5. रेखादेवी पत्नी स्व. श्री सुठाराम, जाति—मेघवाल, निवासी—जीरावल, तहसील— रेवदर

“प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970”

उपस्थिति:

1. परोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की ओर से


—: निर्णय :-

दिनांक 24 जून, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 728/3 रकबा 2—11 बीघा किस्म धोरा भूमि का वर्ष 2004 में कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमि रकबा 2—11 बीघा का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर नामान्तरकरण संख्या 1037 से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/ अप्रार्थीगण का कब्जा काशत लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काशत भी दर्ज नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 728/3 रकबा 2—11 बीघा किस्म धोरा भूमि का सुठाराम पुत्र केसाजी मेघवाल, निवासी— जीरावल को कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी के तौर पर आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित भूमिपेज दो पर


अति. जिला कलेक्टर
सिरौही (राज.)



का मौके पर आवंटिती को कब्जा दिया जाकर जरिये नामान्तरकरण राजस्व रेकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काश्त भी दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण/आवंटिती ने आवंटन का शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अप्रार्थीया के जवाब एवं विधिक दृष्टान्त 2017 RBJ Page 31-35, RBJ(8) 2001 Page 125-129 & 593-595, RBJ (13) 2006 Page 216-222, RBJ (13) 2006 Page 11-15, 2020 RBJ 648-650, RBJ 2020 Page 765-768 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 728/3 रकबा 2-11 बीघा किस्म धोरा भूमि का सुठाराम पुत्र केसाजी मेघवाल, निवासी-जीरावल को विधि अनुसार आवंटन किया जाकर कब्जा सुपर्द किया गया था, तब से आवंटिती एवं आवंटिती की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण उक्त आवंटित भूमि खसरा संख्या 728/3 रकबा 2-11 बीघा पर काबिज होकर काश्त करते आ रही है एवं मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि में काफी रकम खर्च कर काश्त योग्य उपजाऊ बनाया है। उक्त आवंटित भूमि पर बरसाती खेती की जाती है एवं विगत कुछ वर्षों में बारीश कम होने की वजह से उक्त आवंटित भूमि पर काश्त नहीं हो पाई है। खसरा गिरदावरी में काश्त का इन्द्राज करने का दायित्व पटवारी हल्का का है। यदि पटवारी द्वारा काश्त दर्ज नहीं की गई है तो इस कारण से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन के 03 वर्ष बाद आवंटिती स्वतः ही आवंटित भूमि का खातेदार बन जाता है। अप्रार्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी का नामान्तरकरण दायर करने हेतु कई बार निवेदन किया, लेकिन प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं की गई। यह कि अप्रार्थीगण, गरीब भूमिहीन काश्तकार है, जिसके पास उक्त आवंटित भूमि के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का वर्ष 2004 में आवंटन हुआ था एवं उक्त भूमि का आवंटन हुए 22 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं आवंटित भूमि में अप्रार्थीगण के समस्त हक अधिकार निहित हो गये हैं। आवंटन के इतने वर्षों की लम्बी अवधि के बाद आवंटन को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं उक्त आवंटित भूमि के अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 728/3 रकबा 2-11 बीघा किस्म धोरा भूमि का वर्ष 2004 में श्री सुठाराम पुत्र केसाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- जीरावल को उपखण्ड अधिकारी, रेवदर के आदेश क्रमांक: 1622 दिनांक 22-12-2004 के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था एवं उक्त आवंटित भूमि का आवंटिती को कब्जा सुपर्द किया जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 1037 दिनांक 19-2-2005 के द्वारा आवंटित भूमि आवंटिती के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर गैर खातेदार दर्ज हुई। इस संबंध में प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का यह कथन है कि "आवंटित भूमि आज भी गैर खातेदारी दर्ज है, तब से आज तक आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त लगातार नहीं चला आ रहा है व मौके पर आज भी कब्जा नहीं है एवं काश्त भी दर्ज नहीं है।" प्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि "आवंटिती/अप्रार्थीगण ने आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है।"

.....पेज तीन पर

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत भाग पर और शेष क्षेत्र पर दूसरे वर्ष में काश्त करनी आवश्यक है। चूंकि उक्त आवंटित भूमि पर आवंटिती/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं वर्तमान में भी प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार, आवंटिती/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्त का उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी तहसीलदार, रेवदर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी, अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम जीरावल, पटवार हल्का जीरावल के खसरा संख्या 728/3 रकबा 2-11 बीघा किस्म धोरा भूमि का श्री सुठाराम पुत्र केसाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- जीरावल को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 जून, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिराही